



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, गनिवार, 18 मार्च, 2000/28 फाल्गुन, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कारण वताघो नोटिस

शिमला-9, 7 मार्च, 2000

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 72/98-तकलेच-4.—यह कि श्री जवाहर लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत तकलेच विकास खण्ड रामपुर जिला शिमला को उपायुक्त शिमला द्वारा आदेश संख्या पी० सी० एच०-एच० एम० एल० (4)-177/85-2073-88 दिनांक 3-10-98 निम्नलिखित आरोपों में संलिप्त पाए जाने के कारण प्रधान पद से निलम्बित किया गया :—

## 1. खेल मंडान हाई स्कूल तकलेच :

इस योजना हेतु प्रधान द्वारा 2000/- रुपये मूल्य की पेशगी प्राप्त की गई। प्रधान के ध्यान अनुसार उन द्वारा इस गांधी की अदायगी एन० एस० एस० के विद्यार्थियों को की गई है लेकिन प्रधान द्वारा आज तक इस बारे कोई भी विल/वाऊचर पंचायत को प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही इस कार्य का मूल्यांकन करवाया गया। इसके अतिरिक्त एन० एस० एस० के विद्यार्थी जहां कहीं भी कोई कार्य करते तो वह कार्य एक जन सेवा होती है न कि मजदूरी प्राप्त करने हेतु। अतः स्पष्ट है कि प्रधान द्वारा मूल्य 2000/- रुपये का छलहरण किया गया है।

## 2. ग्राम सेवक हट तकलेच :

इस योजना हेतु प्रधान द्वारा मूल्य 6000/- रुपये की पेशगी प्राप्त की गई जिसमें प्रधान द्वारा 25 बैग सीमेंट क्रय किए गये। 25 बैगों में से 12 बैग मोका पर सैट/खराब गये गए तथा शेष सीमेंट का प्रधान द्वारा कोई भी हिमाचल पंचायत को नहीं दिया गया। यह योजना अभी भी अधूरी पड़ी है। अतः प्रधान से मू० 6000/- रुपये की वसूली योग्य है।

### 3. मिडल स्कूल दरवाज़ा :

उक्त योजना हेतु प्रधान द्वारा मूल्य 18000/- रुपये प्राप्त किए गए। प्रधान द्वारा योजना पर कोई भी धनराशि खर्च नहीं की गई और सिर्फ 5000/- रुपये ही पंचायत निधि में वापिस जमा पाए गए। शेष 13000/- रुपये का प्रधान द्वारा कोई भी हिसाब पंचायत को नहीं दिया गया। अतः प्रधान से मु0 13000/- रुपये काबले वसूली है।

### 4. पंचायत स्टाल तकलेच :

पंचायत स्टाल तकलेच के निर्माण हेतु प्रधान द्वारा मु0 18000/- रुपये प्राप्त किए गए। प्रधान द्वारा यह राशि पंचायत स्टाल पर खर्च करके स्कूल भवन निर्माण हेतु व्यय की गई जिसके सबूत में प्रधान द्वारा मु0 11748/- रुपये का मस्ट्रोल तथा मु0 7788 रुपये के बिल दिनांक 22-1-98 को पंचायत को प्रस्तुत किए गए हैं। प्रधान द्वारा ए6 योजना की स्वीकृत धनराशि दूसरी योजना में व्यय की गई है जो कि एक नए कानूनी कारवाई है। इस कार्य हेतु प्रधान द्वारा कोई भी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

### 5. ट्राइसम शाप तकलेच :

इस कार्य हेतु मु0 75000 रुपये स्वीकृत हुए थे जिसमें 1 खण्ड विकास अधिकारी रामपुर द्वारा सिर्फ 68000/- रुपये ही अदा किए गए। प्रधान द्वारा मूल्य 68000/- रुपये का व्यय करते हुए 10वें विस्तारयोग में से मु0 25000/- रु0 और अधिक व्यय किए गए। इस प्रकार प्रधान द्वारा योजना पर मु0 93000/- रुपये का व्यय दर्शाया गया है जबकि इस योजना का मूल्यांकन सिर्फ 88558/- रुपये ही हुआ है। प्रधान से मु0 12442/- रुपये वसूली योग्य शेष है।

### 6. नगद शेष :

ग्राम अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है कि जांच के दिनांक तक प्रधान से मु0 5813.70/- रुपये नगद शेष के रूप में थे जो कि अभी भी वसूली योग्य है।

### 7. जवाहर रोजगार योजना रोकड़ राशि :

मुरम्मत पंचायत घर व पंचायत स्टाल हेतु प्रधान द्वारा दो किस्तों में मु0 7000/- रुपये प्राप्त किए गए। प्रधान के व्यान अनुसार उन द्वारा पंचायत घर व स्टाल का मुरम्मत कार्य पूर्ण करवाया गया है जिसके बिल व वाऊचर उन द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंप दिए गए हैं लेकिन प्रधान द्वारा इन योजना का अभी तक मूल्यांकन नहीं करवाया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रधान द्वारा वास्तव में ही इस योजना में से मरनारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है अथवा नहीं।

उपरोक्त आरोपों की राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत विभागीय जांच करवाई गई। जिसमें जांच अधिकारी ने उपरोक्त आरोपों की पुष्टि की है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) में प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए श्री जवाहर लाल, प्रधान (नि0) ग्राम पंचायत तकलेच विकास खण्ड रामपुर जिला शिमला को कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान पद से निष्कासित करने हुए न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया जाए तथा उन्हें उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत 6 वर्ष की अवधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने से विवर्जित किया जाए। श्री जवाहर लाल, प्रधान (नि0) ग्राम पंचायत तकलेच का जावा आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर-2 अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए अथवा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
आयुक्त एवं सचिव।